KAAV INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
KIJAHS/APR-JUN2017/VOL-4/ISS-2/A17 PAGE NO-95-101
ISSN:2348- 4349 IMPACT FACTOR(2017) – 7.9183
www.kaavpublication.org

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति दक्षिणी: एशिया के संदर्भ में

[1]नन्द लाल खटीक

[1]शोधार्थी,राजनीति विज्ञान विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,उदयपुर

दक्षिणी एशिया वर्तमान काल में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्र–बिन्दु है। दक्षिणी एशिया प्राचीनकाल से ही अपनी सांस्कृतिक समन्वयता का प्रतीक रहा है। इसी कारण इस क्षेत्र की पृथक पहचान एवं भूमिका रही है। दक्षिणी एशिया की भौगोलिक स्थिति के आधार पर इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालद्वीप को शामिल किया जाता है। लेकिन अधिकांश पश्चिमी विचारक अफगानिस्तान को भी दक्षिणी एशिया में सम्मिलित करते है। दक्षिणी एशियाई देशों में नेपाल को छोड़कर अन्य सभी देशों पर अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण था जिसके कारण इन देशों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याएँ पराधीनता से ही विरासत में मिली थी। दक्षिणी एशिया जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। दक्षिणी एशियाई देशों में प्राकृतिक संसाधन, जनशक्ति, प्रतिभा आदि की कमी नहीं है फिर भी ये देश गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, आतंकवाद आदि अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहे हैं। दक्षिणी एशिया का विस्तार लगभग 45 लाख वर्ग किमी. क्षेत्र में है। जिसमें विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 वां भाग निवास करता है। विदेश नीति के निर्धारण में प्रत्येक राज्य को अपने पड़ोसी देशों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि पड़ोसी राष्ट्रों की नीतियाँ सदैव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती रहती हैं भारत की विदेश नीति पर पड़ोसी राष्ट्रों की नीतियों का प्रभाव प्रारंभ से ही रहा है। भारत दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों में आकार, जनसंख्या, संसाधन प्रौद्योगिकी आदि आधारों पर सबसे बड़ा देश है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालद्वीप, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान है जो दक्षिणी एशिया में स्थित है। दक्षिणी एशियाई देशों में विशेषकर पाकिस्तान के साथ प्रारंभ से ही सम्बन्धों में कटुता रही है।भारत व पाकिस्तान दोनों देश स्वतंत्रता के समय एक साथ ही अस्तित्व में आये थे। विभाजन के बाद यह आशा की गई थी कि भारत में शान्ति स्थापित हो जाएगी, परन्तु पाकिस्तान की विदेश नीति का आधार ही भारत विरोधी रहा है क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण ही साम्प्रदायिक आधार हुआ था। भारत व पाकिस्तान के बीच निम्न समस्याएँ है जिसके कारण मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना कठिन है। जैसे कश्मीर विवाद, हैदराबाद, जूनागढ़ विवाद, शरणार्थियों की समस्या, जल विवाद, आतंकवाद आदि। स्वतंत्रता के पश्चात दोनों देशों के बीच सम्बन्ध उतार–चढ़ाव पूर्ण रहे हैं ये सम्बन्ध इतने तनावपूर्ण रहे है कि दोनों देशों के बीच चार युद्ध हो चुके है।भारत तथा पाकिस्तान के बीच सबसे प्रमुख समस्या कश्मीर है जो दोनों देशों की सरकारों के लिए चुनौती बनी हुई है। के.आर. पिल्लै ने कहा था कि ''निश्चित ही भारत के पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध हमारी विदेश नीति का सबसे अधिक देखने योग्य मुख्य भाग रहा है।'' भारत ने पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने का कार्य प्रारम्भ से ही किया था लेकिन पाकिस्तान के नकारात्मक दृष्टिकोण ने वांछित परिणाम प्राप्त करने में भारत को कभी भी सफल नहीं होने दिया है।

नॉरमन डी पॉमर ने कहा है कि – ''भारत के पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों ने भारत की समस्त विदेश नीति के प्रायः सभी पक्षों तथा इसके सारे अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रभावित कर रहा है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत–पाक सम्बन्धों में कई उतार–चढ़ाव आए है। जिनमें परमाणु परीक्षण, बस कूटनीति, लाहौर घोषणा–पत्र कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की असफलता, क्लिंटन की भारत यात्रा से उत्पन्न स्थिति आदि प्रमुख घटनाओं ने भारत–पाक सम्बन्धों का निर्धारण किया और दुर्भाग्यवश यह निर्धारण नकारात्मक दिशा में हुआ हैं आज भी यह वातावरण नकारात्मक बना हुआ है।'' वाजपेयी ने भारत की विदेश नीति को गुटनिरपेक्षता पंचशील पर आधारित विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक विकास वाली नीति तथा परमाणु विकल्प अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ मधुर सम्बन्धों वाली नीति अपनाई थी।वाजपेयी ने मई 1998 में पोकरण में परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु क्लब में शामिल किया था। वाजपेयी ने कहा कि सी.टी.बी.टी. भेदभाव मूलक संधि है क्योंकि परमाणु हथियार सम्पन्न देशों को उन्नत तकनीकी क्षमता के साथ अपना नाभिकीय कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति देता है। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा कि 'भारत अपनी नाभिकीय क्षमता का प्रयोग बहुत ही अनिवार्य हुआ तो आत्मरक्षा के लिए करेगा। वाजपेयी काल में भारत–पाकिस्तान सम्बन्धों में सुधार के

Copyright © 2017 Published by kaav publications. All rights reserved www.kaavpublications.org

लिए प्रथम प्रयास 1998 में कोलम्बों सार्क शिखर सम्मेलन में भारत तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों द्वारा एक बैठक की गई थी लेकिन परिणाम शून्य ही रहा। पाक ने कश्मीर मुद्दा उठाकर विवाद बढ़ा दिया था साथ ही पाक ने परमाणु युद्ध छिड़ने की धमकी भी दी थी। ''सार्क के माध्यम से पाक का इस तरह का बयान दोनों देशों के सम्बन्धों को तनावपूर्ण दिया था।''20 फरवरी 1999 को प्रधानमंत्री वाजपेयी ने बस द्वारा लाहौर यात्रा की इसी दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी भेंट की थी। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 'लाहौर घोषणा पत्र', संयुक्त वक्तव्य जारी किया था। नवाज शरीफ ने आतंकवाद की आलोचना करते हुए इसकों समाप्त करने का निश्चय प्रकट किया था। संयुक्त वक्तव्य जारी करते हुए कहा गया कि समय–समय पर दोनों देशों के विदेशमंत्री बैठके करेंगे, जिसमें आपसी मुद्दों, वीजा प्रक्रिया को उदार बनाने आदि पर चर्चा की जाएगी। लाहौर यात्रा के तुरन्त बाद भारत को कारगिल संकट मिला था। जिसमें पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारत में कश्मीर के रास्ते प्रवेश करना शुरू किया था, वाजपेयी सरकार ने साहसपूर्ण कार्यवाही करते हुए घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। वाजपेयी ने 20 जून 1999 में घोषणा की थी जब तक घुसपैठ करने वालों को भारतीय क्षेत्र से खदेड़ नहीं दिया जाता हैं तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी।'' कारगिल संघर्ष में पाकिस्तानी सेना की कूटनीति पूरी तरह विफल रही जबकि भारत को सैनिक व कूटनीतिक सफलता प्राप्त हुई थी।वाजपेयी के निमंत्रण पर परवेज मुशर्रफ जुलाई 2001 को भारत यात्रा पर आये थें। मुशर्रफ व वाजपेयी के बीच आगरा शिखर वार्ता हुई जिसमें भारत ने सीमा पार आतंकवाद की समाप्ति पर बल दिया था। परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर समस्या के हल के लिए मध्यस्थता के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका चाहता था। पाकिस्तान के अड़ियल रवैया के कारण आगरा शिखर वार्ता असफल हो गई। जिसमें कोई संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया और न ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए थे।सितम्बर–अक्टूम्बर 2001 में अफगानिस्तान समस्या से निर्मित वातावरण ने भारत–पाक सम्बन्धों को उलझनपूर्ण बना दिया जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। 13 दिसम्बर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ जिसमें स्पष्ट प्रमाण मिले कि इसमें पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का हाथ था। भारत ने भारतीय उच्चायुक्त तथा स्टाफ को पाकिस्तान से वापस बुला लिया व भारत–पाकिस्तान रेल सेवा व बस सेवा को बंद कर दिया गया था। 13 दिसम्बर, 2001 के आतंकवादी हमले के बाद वाजपेयी ने कहा कि – ''भारत को संसद पर हमले के तुरन्त बाद ही पाकिस्तान को उचित जवाब दे देना था, मगर तब समूचे विश्व ने भारत से संयम बरतने का आग्रह किया।'' 20 जनवरी 2003 को पाकिस्तान ने पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का मुद्दा उठाने का असफल प्रयास किया परन्तु प्रधानमंत्री वाजपेयी ने इसके विरूद्ध वास्तविक समस्या आतंकवाद तथा सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने पर बल दिया था। भारत–पाक सम्बन्धों में 2003 से कूटनीतिक प्रक्रिया पुनः शुरू हुई। अजीत खान को भारत में पाक के उच्चायुक्त तथा श्री शिवशंकर मेनन को पाक में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। 11 जुलाई 2003 को नई दिल्ली–लाहौर बस सेवा पुनः शुरू की गई।

भारत–पाक निकटतम पड़ौसी होने के बावजूद भी दूर के पड़ौसी बने हुए है। सजातीय, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक आधारों पर सबसे अधिक निकट है किन्तु राजनीतिक स्थिति एवं विदेश नीति के सम्बन्ध में भारत से काफी दूर है। भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप अनावश्यक रूप से भड़की साम्प्रदायिक हिंसा से भाई–भाई के बीच रक्त की धाराएँ निकली थी और 1948, 1965, 1971 और 1999 में कारगिल सहित चार युद्ध भी हुए और आज भी सम्बन्धों की प्रक्रिया अटकी हुई है। पाकिस्तान–भारत के विरूद्ध विद्रोह एवं आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत की सुरक्षा और अखण्डता को तोड़ने का प्रयास करता रहता है। कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को प्रशिक्षण और पैसों के साथ भाड़े के सैनिक भेज रहा है जिससे आतंकवादी गतिविधियों में तीव्रता आई है। क्योंकि पाक भारत को युद्ध में परास्त नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बांग्लादेश के साथ सम्बन्धों के विकास में गतिशील कार्य किया था। मई 1998 को जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तब बांग्लादेश सरकार ने संयमपूर्ण नीति अपनाई। जून 1998 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पोकरण विस्फोट के बाद भारत की सरकारी यात्रा की थी तथा शेख हसीना ने भारत के सम्प्रभुता अधिकार के अन्तर्गत परमाणु परीक्षण को उचित माना था। बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्वीकार किया कि प्रत्येक देश को आत्मरक्षा एवं सुरक्षा के लिए इस तरह के कदम उठाने की स्वतंत्रता हैं। कश्मीर समस्या पर किसी दूसरे देश की मध्यस्था के लिए शेख हसीना ने इंकार कर दिया था।

वाजपेयी द्वारा कलकत्ता–ढाका बस सेवा का आरम्भ अप्रैल, 1999 में किया था और विधिवत रूप से शुभारम्भ 19 जून 1999 को किया गया था। इसी अवसर पर वाजपेयी बांग्लादेश की यात्रा पर गए और शेख हसीना से उच्च स्तरीय वार्ता भी की थी। फरवरी 2000 में बांग्लादेश को सरल कर्ज देने की सहमती प्रकट की। फरवरी 2001 में भारत–बांग्लादेश कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई जिसमें निम्न समझौते किए गए थे–

1. कूटनीतिक पासपोर्ट धारकों को वीजा प्राप्त करने की छूट दी गई।
2. व्यापारियों, विद्यार्थियों तथा शोधकर्ताओं को एक वर्ष के लिए बहुपक्षीय आधार पर प्रवेश की सुविधाएँ दी गई।
3. परमिट धारकों को वर्ष दर वर्ष वीजा देने की व्यवस्था किए जाने का निर्णय लिया गया।

भारत तथा बांग्लादेश ने जनवरी 2002 में काठमाण्डु शिखर सम्मेलन के दौरान वार्तालाप करके आर्थिक–व्यापारिक सहयोग बढ़ाने का विश्वास प्रकट किया तत्पश्चात् फरवरी–मार्च 2002 में काठमाण्डु शिखर सम्मेलन के समय वार्तालाप कर आर्थिक–व्यापारिक सहयोग बढ़ाने का विश्वास प्रकट किया गया था। लेकिन फरवरी मार्च 2002 में गुजरात प्रांत में

Copyright © 2017 Published by kaav publications. All rights reserved www.kaavpublications.org

साम्प्रदायिक हिंसा फैलने से बांग्लादेश के कुछ संगठनों ने भारत विरोधी प्रचार किया। इसी समय बांग्लादेश का झुकाव चीन की तरफ बढ़ा। फरवरी 2003 में भारत–बांग्लादेश सीमा पर गोलाबारी की गई जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा।प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से दोनों देशों के बीच नजदीकीयाँ आई थी, जिसके कारण दोनों देशों की सीमाओं पर व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ी। बांग्लादेश को होने वाले निर्यात में वृद्धि हुई है और बांग्लादेश से सम्बन्ध बढ़ाने के लिये वाजपेयी ने 19 सितम्बर 2003 को अगरतल्ला–ढाका के बीच बस सेवा प्रारम्भ की। जबकि कोलकता–ढाका बस सेवा पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी थी। वाजपेयी के नेतृत्व में बांग्लादेश से मधुर सम्बन्ध बनाने का भरसक प्रयास किया गया जिसमें कुछ घटनाओं को छोड़कर दोनों देशो के बीच सहयोगपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधियों की यात्राओं ने मधुर सम्बन्ध बनाए एवं आतंकवाद की समाप्ति पर विशेष बल दिया गया जिसमें आशिंक सफलता भी प्राप्त हुई।

श्रीलंका भारत के दक्षिणी में स्थित है। भारत व श्रीलंका दोनों ही उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं तथा दोनों देशों के संबंधों में स्वतंत्रता के बाद उतार–चढ़ाव आते रहे है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में श्रीलंका से सम्बन्ध सुधारने का कार्य किया गया। भारत के परमाणु परीक्षण 'पोकरण–2' पर श्रीलंका ने संतुलित प्रतिक्रिया प्रकट की किन्तु कुछ समय पश्चात श्रीलंका के विदेशी मंत्रालय ने इस संबंध में ''दक्षिणी एशिया में परीक्षण एक चिन्ता का विषय'' कहकर अपने विचार व्यक्त किए।

श्रीलंका की राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारतुंग 27 दिसम्बर 1998 को तीन दिवसीय भारत यात्रा पर आई और भारत व श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की थी। श्रीलका दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ में पहला ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया था। इस समझौते के अनुसार भारत 3 वर्ष एवं श्रीलंका 8 वर्षों में सभी आयात शुल्कों को हटा लेगा और दोनों के बीच भारत श्रीलंका फाउण्डेशन की स्थापना की जायेगी। भारत की तरफ से वित्त मंत्री यशवन्त सिन्हा व श्रीलंका के वित्त मंत्री श्री लक्ष्मण ने हस्ताक्षर किए थे। यह फाउण्डेशन कला, संस्कृति, व्यापार, वाणिज्य और विज्ञान के क्षेत्रों में दोनों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद देगा। श्रीलंका के शान्ति प्रयासों में अप्रैल 2000 की भीषण घटना ने समस्त परिदृश्य को ही बदल दिया था। लिट्टे द्वारा श्रीलंका के सैन्य ठिकानों पर 21 अप्रैल, 2000 में नियंत्रण करना, श्रीलंका के इतिहास की सबसे भीषण घटना थी। जाफना युद्ध से निपटने के लिए श्रीलंका सरकार ने मित्र देशों से अपील की थी। जिसमें सर्वप्रथम भारत ने समर्थन किया। भारत के सामने 1987 वाली स्थिति पुनः आ गई। जिसमें भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। फिर वही परिस्थितिया आ गई थी तो भारत सरकार ने हस्तक्षेप नीति की अनुशंषा करते हुए किसी भी प्रकार की सैन्य सहायता देना स्वीकार किया। इसमें भारत सरकार की कुछ मजबूरियाँ थी जो किसी भी प्रकार के सक्रिय हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं थी। अगर भारत श्रीलंका के सैनिकों की सुरक्षित वापसी के लिए किसी प्रकार का सैन्य हस्तक्षेप करता तो पुनः एक बार लिट्टे तथा भारतीय सेना के मध्य युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इसके अलावा केन्द्र की एन.डी.ए. सरकार में प्रमुख सहयोगी दल तमिलनाडु की डी.एम.के. पार्टी भी थी जिसने श्रीलंका की वर्तमान तमिल समस्या पर भारत सरकार पर सैन्य हस्तक्षेप नहीं करने का दबाव बनाए रखा।विदेश मंत्री जसवन्त सिंह ने कहा कि – ''भारत श्रीलंका की समस्या का समाधान उसकी एकता और अखण्डता को बनाए रखते हुए ही देखना चाहता है। हम श्रीलंका में शान्ति स्थापना के लिए अपना हर सम्भव योगदान देने के लिए भी तैयार है किन्तु जहाँ तक सैन्य सहायता का प्रश्न है तो हम ऐसा नहीं कर सकते है। वाजपेयी जी ने भी यह घोषणा की थी कि हम श्रीलंका में मानवीयता के आधार पर अन्य किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार हैं।

भारत–श्रीलंका सम्बन्धों के निर्धारण में तमिलनाडु की भुमिका सदैव ही महत्त्वपूर्ण रही है। 12 मई 2000 को करूणानिधी ने विधानसभा में अपने भाषण में जहाँ एक ओर लिट्टे का समर्थन किया वहीं दूसरी और उन्होंने कहा कि – ''इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि भारत की भूमि से लिट्टे को अपनी गतिविधियाँ संचालित करने के लिए डी.एम. के. से कोई समर्थन मिलेगा।'' श्रीलंका समस्या समाधान के लिए 'चेक मॉडल' प्रस्तुत कर दिया। करूणानिधी द्वारा प्रस्तुत इस चेक मॉडल के सुझाव की श्रीलंका सरकार ने निन्दा की तथा प्रतिक्रिया स्वरूप श्रीलंका के प्रवक्ता मंगला समवीरा ने कहा कि ''श्रीलंका के विभाजन का अर्थ भारत के विभाजन की शुरूआत होगी। करूणानिधी का विवादास्पद सुझाव सम्बन्धों में हानिकारक हो सकता था किन्तु सकारात्मक परिणाम विदेश मंत्री जसवंत सिंह की श्रीलंका यात्रा के रूप में देख सकते है जो 11 जुलाई 2000 को श्रीलंका यात्रा पर गये और कहा कि ''भारत आज भी पूर्व की ही भांति श्रीलंका की क्षेत्रीय अखण्डता का समर्थक है।'' जसवंत सिंह ने कहा कि – ''हम तमिल समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान के पक्षधर है।''वाजपेयी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रमसिंधे को आश्वस्त किया कि ''वह शान्ति वार्ता को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं इस सम्बनध में विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने कहा कि भारत ने शांति प्रक्रिया को हमेशा से प्रोत्साहित किया है और वह न केवल श्रीलंका सरकार के साथ बल्कि नार्वे की सरकार के साथ भी बराबर सम्पर्क में है।''

वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में भारत और श्रीलंका के सम्बन्ध शान्तिपूर्ण रहे। वाजपेयी काल में विदेशी नीति पड़ौसी देशों के राजनैतिक मुद्दों तक ही सीमित नहीं होकर व्यापारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों तक विस्तार रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच सम्बन्धों में रक्षा क्षेत्रों तक विस्तार हुआ था। रक्षा क्षेत्र में विस्तार के लिए व्यापक विचार विमर्श की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से श्रीलंका से 4 सदस्यीय प्रतिनिधी मण्डल रक्षा सचिव हर्थ की अध्यक्षता में 14 जनवरी 2004 में भारत आया था।''वाजपेयी काल में दोनों राष्ट्रों के सम्बन्ध संतुलित और सौहार्दपूर्ण

Copyright © 2017 Published by kaav publications. All rights reserved www.kaavpublications.org

रहे। आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप और असंलग्नता की विदेश नीति का अनुसरण करते हुए दोनों देशों के सम्बन्धों को नई दिशा व ऊँचाई प्रदान की है। नई विचारधारा व विदेश नीति के साथ से लम्बे समय तक सत्ता में रही एन.डी.ए. सरकार के पतन के साथ ही दोनों राष्ट्रों के सम्बन्धों के एक युग का अंत हो गया। भारत व श्रीलंका में सरकारें बदलती रहती है किन्तु द्विपक्षीय सम्बन्ध सदैव शान्त व स्थिर रहे है न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अनेक वैश्विक मंचों पर भी दोनों राष्ट्रों ने एक–दूसरे को सहयोग प्रदान किया है इसमें चाहे 'सार्क' हो या 'नाम' हो चाहे आतंकवाद या सुरक्षा परिषद् में भारत की सदस्यता हो। श्रीलंका ने प्रत्येक मुद्दे पर अच्छे मित्र की भूमिका निभाई है ओर भारत ने भी हमेशा से ही श्रीलंका की एकता व अखण्डता का समर्थन किया है। इन्हीं सकारात्मक आधारों पर चलकर भविष्य में भी भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय सम्बन्धों को मजबूत बनाया जा सकता है।भारत एवं नेपाल के सम्बन्ध प्राचीन काल से रहे है। रामायण काल से ही दोनों देशों के बीच सम्बन्ध थे। भारत एवं नेपाल इतिहास, भूगोल, धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक आदि आधारों पर एक साथ रहने को बाध्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी छोटा होते हुए भी नेपाल भारत के लिए काफी महत्त्वपूर्ण रहा है। भारत एवं चीन के बीच मध्यवर्ती देश की भूमिका में होने के कारण इसका सामरिक महत्त्व भी है। वाजपेयी के नेतृत्व में छक। सरकार में भारत एवं नेपाल ने 'पारगमन संधि' पर हस्ताक्षर किए।

दिसम्बर 1999 में भारतीय नागरिक हवाई सेवा का विमान आई.सी. 814 जो कि काठमाण्डु से दिल्ली आते हुए अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद नेपाल जाने वाली हवाई सेवा को बन्द कर दिया गया। फरवरी 2000 में भारत व नेपाल के बीच 'साझे सीमा कार्यकारी समूह' की तीसरी बैठक हुई जिसमें दोनों देश अपने–अपने भू–क्षेत्र को दुसरे के विरूद्ध प्रयोग नहीं करने देंगे। मई 2000 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने हवाई सेवाओं को पुनः शुरू करने का समझौता किया।भारत व नेपाल के नेताओं ने जनवरी 2000 में सार्क सम्मेलन के दौरान काठमाण्डु में आपसी सम्बन्धों को व्यापक व गतिशील बनाने का निर्णय दोहराया। नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र ने 2002 में भारत की यात्रा की थी और भारत ने नेपाल सरकार द्वारा माओवादियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान में सहयोग देने का आश्वासन दिया। भारत व नेपाल के बीच मार्च 2003 में प्रत्यपर्ण संधि को व्यापक बनाकर आतंकीय अपराधों व वित्तीय अपराधों पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई थी। भारत व नेपाल के विदेश सचिवों की उपस्थिति में 23 फरवरी 2004 को समझौता हुआ। जिसमें दोनों देशों की राजधानियों को जोड़ने वाले 14 प्रमुख मार्गों पर बस सेवा प्रारम्भ करना प्रमुख था। भारत के साथ सम्बन्धों का विकास करना नेपाल की भौगोलिक, व्यापारिक और सामाजिक आवश्यकता है। परन्तु नेपाल में बढ़ती माओवादियों एवं उग्रवादियों की हिंसक कार्यवाहियाँ भारत–नेपाल सम्बन्धों की विकास की प्रक्रिया को शिथिल बना रही है। वाजपेयी ने नेपाल की सम्प्रभूता, अखण्डता का समर्थन करते हुए नेपाल की राजनीतिक गतिविधियों को आन्तरिक मुद्दा स्वीकार किया है। नेपाल में जारी माओवादी हिंसा की समाप्ति भारत चाहता है तथा इस संकट में नेपाल की सहायता करने के लिए तत्पर है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होना चाहता है।प्रधानमंत्री वाजपेयी ने नेपाल के साथ सम्बन्धों में विशेष प्राथमिकता दी है लेकिन कुछ मुद्दों पर पारदर्शिता एवं खुलेपन का अभाव रहा है जिससे दोनों देशों के सम्बन्धों में उतार–चढ़ाव रहा है। नेपाल ने अनेक बार भारत की उपेक्षा करके साम्यवादी चीन के साथ समझौते किए। नेपाल में चीन की गतिविधियाँ भारत विरोधी रही है। नेपाल द्वारा काठमाण्डु लहासा सड़क मार्ग बनाने के सम्बन्ध में चीन से समझौता भारत विरोधी कार्य था। नेपाल का यह दृष्टिकोण है कि नेपाल को शान्ति क्षेत्र घोषित किया जाए इसमें नेपाल का उद्देश्य यह है कि भारत के प्रभाव और विशिष्ट क्षेत्र को नकारना है जिसे वह राष्ट्रीय विकास में बाधक मानता है। नेपाल, भारत व चीन के साथ सम दुरी सिद्धान्त के आधार पर सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। जिससे चीन को भी सन्तुष्ट किया जा सके लेकिन भारत इस सम दुरी सिद्धान्त को नहीं मानता है। वाजपेयी ने पड़ोसियों के साथ मित्रता को सुदृढ़ बनाने की नीति का पालन किया है तथा नेपाल के साथ सम्बन्धों को मजबुत व मधुर बनाने की पूर्ण कोशिश की है।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने भूटान के साथ 8 अगस्त 1949 में संधि की जिसके अन्तर्गत भूटान सरकार विदेशी मामलों में भारत की सलाह के अनुसार कार्य करेगी तथा भारत भी भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। 1971 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता में भूटान का नाम प्रायोजित किया तथा इन सभी धारणाओं को झुठला दिया कि भारत भूटान पर आँख रखता है। इसी घटना के बाद भारत–भूटान संबंध क्रमशः गहन होते गए। ''भूटान भारत के साथ अपने सम्बन्धों से पूर्णतया संतुष्ट है। इसने दूसरे देशों के साथ कुटनीतिज्ञ सम्बन्धों की स्थापना करने में परहेज किया है। यह विशेषतया चीन की टोह से दूर ही रहा है।'' प्रधानमंत्री वाजपेयी ने आश्वासन दिया कि भारत भूटान के हितों को ध्यान में रखते हुए हमेशा सहायता देता रहेगा। भूटान में पन बिजली परियोजनाओं एवं कृषि औद्योगिक आधारभूत ढांचे को विकसित करना चाहता है। मई 1999 में भूटान नरेश ने भारत की यात्रा की तथा दोनों देशो के बीच सम्बन्धों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया।

टी.एन.कौल ने कहा कि – ''हमने नेपाल में जो गलती की थी उससे अब बचना चाहिए तथा यह नहीं समझना चाहिए कि छोटे देश हमेशा उसके मित्र बने रहेंगे तथा भारत को बड़े भाई जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे देश छोटी–छोटी बातों को महसूस कर लेते है। वे बड़े गर्वीले है, संवेदनशील है तथा उन्हें भी दुःख पहुँच जाता है। हमें उनकी संवेदनाओं का आदर करना चाहिए तथा उनका विश्वास जीतना चाहिए। उन पर कई प्रकार के दबाव होते है, कई प्रकार के आंतरिक तनाव होते है जिन्हें वे भारत जैसे अच्छे पड़ोसी की अनुभूति तथा सम्मान के अभाव में सहन नहीं कर

Copyright © 2017 Published by kaav publications. All rights reserved www.kaavpublications.org

सकते।''भूटान नरेश जिग्में वांगचुक ने 14 सितम्बर 2003 में पाँच दिवसीय भारत यात्रा की थी। यह यात्रा दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को मजबूती प्रदान करने में उपयोगी रही है। भारत–भूटान सीमा पर उग्रवादी व आतंकवादी गतिविधियाँ दोनों देशों के बीच चिन्ता का विषय है। नरेश ने भारत को विश्वास दिलाया कि भूटान आतंकवादियों पर कठोर कार्यवाही करेगा। दिसम्बर 2003 में भूटान की सेना ने न्स्थ्।ए छक्थ्ठ भूटान की धरती पर विद्यमान शिविरों के विरूद्ध सैनिक अभियान आरम्भ किया था। भूटान की इस कार्यवाही की वाजपेयी ने प्रशंसा की थी। वाजपेयी ने भूटान को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। नेपाल की भांति भूटान में लोकतंत्रात्मक स्वरूप को अपनाया जा रहा है। 31 दिसम्बर 2007 में ऊपरी सदन के लिए मतदान भी हुआ जो सकारात्मक कदम है क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रवादी देश है और लोकतंत्र की स्थापना का पक्षधर रहा है। भूटान भारत से अधिक नजदीक रहा है और भूटान की विदेश नीति भारत प्रभावित रही है क्योंकि भूटान को यह आशंका है कि चीन ने जिस प्रकार तिब्बत पर अधिकार किया है उसी प्रकार भूटान पर भी अधिकार कर सकता है। भूटान में भी लोकतंत्र की स्थापना हो रही है इनसे भारत की स्थिति अधिक मजबूत होगी। भारत के पड़ोस में लोकतंत्र जितना मजबूत हो, उतनी ही भारत की ताकत बढ़ती है।मालद्वीप दक्षिणी एशिया का एक बहुत ही छोटा देश है तथा अन्य देशों से अधिक दूर है। मालद्वीप दक्षिणी भाग में स्थित छोटा सा द्वीपीय देश है जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय सक्रियता बहुत ही कम है लेकिन हिन्द महासागर में स्थित होने के कारण एवं सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 'डियागों गार्सिया' के नजदीक होने के कारण इसका सामरिक महत्त्व अधिक है। सार्क संगठन का सदस्य होने से दक्षिणी एशिया में इसका महत्त्व बढ़ जाता है।प्रधानमंत्री वाजपेयी ने सार्क शिखर सम्मेलन (2002) व 12वें शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद (2004) में मालद्वीप के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम के साथ प्रधानमंत्री वाजपेयी ने वार्तालाप करते हुए दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को प्रभावी बनाने पर बल दिया। दोनों देशों के राजनयिकों, शिष्टमण्डलों आदि द्वारा समस्याओं को दूर कर सम्बन्धों में सुधार लाने का भरसक प्रयास किया गया।

सार्क के 11वें शिखर सम्मेलन में अटल बिहारी वाजपेयी ने मालद्वीप में गरीबी उन्मूलन व आतंकवाद के उन्मूलन में मालद्वीप से सहयोग की अपेक्षा की थी। वाजपेयी के नेतृत्व में मालद्वीप के प्रति भारत की विदेश नीति सहयोगपूर्ण एवं समानता पर आधारित रही है। भारत मालद्वीप के विकास में सभी तरह से सहयोग करके चहुमुखी विकास में महत्ती भूमिका निभा रहा है।भारत में मार्च 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन सरकार वाजपेयी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ हुई। उस समय विदेश नीति के समक्ष विभिन्न चुनौतियाँ थी। अतः 11 से 13 मई 1998 में वाजपेयी सरकार द्वारा परमाणु परीक्षण को अंजाम देने से भारतीय विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया था। वाजपेयी के शासनकाल में भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में निरन्तर सुधार होने से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में सुधार हुआ है। परमाणु परीक्षणों के बाद विश्व स्तर पर कुछ देशों ने आलोचना भी की तथा कुछ प्रतिबन्ध भी लगाए गये थे। लेकिन वाजपेयी की कुशल विदेश नीति ने विश्व में अपना लोहा मनवा लिया तथा राष्ट्रीय हित व सम्प्रभुता पर किसी भी प्रकार की आँच नहीं आने दी। विश्व में वाजपेयी ने जो छवि बनाई थी उसी नीति को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपनाने का प्रयास किया पर इसके बाद नरेन्द्र मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने का कार्य शपथ ग्रहण से ही प्रारम्भ कर दिया जिसमें अपने शपथ ग्रहण समारोह में सभी पड़ोसी देशों के शासनाध्यक्षों को आमंत्रित करके वाजपेयी की विदेश नीति को शिखर तक पहुँचाने का कार्य किया हैं।

भारत को भी यह समझना होगा कि एशिया या विश्व में उसकी हैसियत तभी बन सकेगी जब वह दक्षिणी एशिया में प्रभावी भूमिका निभाएगा। भारत प्रत्येक क्षेत्र में दक्षिणी एशिया का नेतृत्व नहीं कर पा रहा हैं। भारत को इस पर विचार करना चाहिए कि पड़ोसी देशों में भारत विरोधी गतिविधियाँ क्यों बढ़ रही है? इन्हें ध्यान में रखकर प्रभावी विदेश नीति लागू करनी चाहिए जिससे विश्व में दक्षिणी एशियाई देशों का नेतृत्व किया जा सकें।

सुझाव

प्रस्तुत शोध पेपर में ''प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति (दक्षिणी एशिया के संदर्भ में)'' में दक्षिणी एशियाई देशों के प्रति अटल बिहारी वाजपेयी की नीति का उल्लेख किया गया है। दक्षिणी एशियाई देशों के साथ भारत सम्बन्धों में उतार–चढ़ाव आते रहे है। वाजपेयी के कार्यकाल में पड़ोसी देशों में राजनैतिक परिवर्तनों का दोर रहा है। भूटान व नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास शुरू हो गए थे।

- प्रारम्भ से लेकर वर्तमान तक भारत–पाक सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे है। मुख्यतः कश्मीर में आतंकवाद को प्रोत्साहन एवं सैन्यीकरण आदि मुद्दे है जो विवाद के कारण है। अतः दोनों देशों को सहयोगपूर्ण सम्बन्ध सस्थापित करके तनावों को कम करने का प्रयास करना चाहिए।
- दक्षिणी एशियाई के देशों को सहयोगपूर्ण नीति अपनाकर अपने संसाधनों का समुचित एवं प्रभावी उपयोग करना चाहिए।
- दक्षिणी एशियाई देशों को व्यापारिक एवं औद्योगिकीकरण के क्षेत्रों में सहयोग करना चाहिए। नेपाल व श्रीलंका जैसे देशों के साथ भारत व्यापार बढ़ा सकता है।

Copyright © 2017 Published by kaav publications. All rights reserved www.kaavpublications.org

- नेपाल व भूटान से सीमेंट व प्राकृतिक गैस तथा कागज बांग्लादेश से तथा रबर श्रीलंका से भारत आयात कर सकता है। इनसे विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर निरर्भरता कम होगी एवं क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में विकासकारी कदम होगा।
- दक्षिणी एशिया में ऊर्जा संसाधनों का प्रचुर भण्डार है जिनका सामुहिक प्रयासों से उपयोगी बनाकर आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है।
- दक्षिणी एशियाई देशों को प्रभावित करने वाली समस्याओं में राजनीतिक एवं सामरिक समस्याओं पर पुनः विचार की आवश्यकता हैं इन समस्याओं को चर्चाओं, वार्तालापों, संवादों आदि के माध्यम से हल करके सहयोगपूर्ण वातावरण निर्मित करना चाहिए।
- आज विश्व आतंकवाद या इसी तरह की प्रवृत्तियों से पीड़ित है। आतंकवाद की कोई सीमा, धर्म एवं देश नहीं होता है। आतंकवाद के उन्मूलन में सभी देशों को सामुहिक प्रयास करना चाहिए।
- दक्षिणी एशिया को आतंकवाद मुक्त करने के लिए सामुहिक रणनीति बनानी होगी। आतंकवाद को एक–दूसरे देश के खिलाफ भड़काना नहीं चाहिए और अपने देश में शरण भी नहीं देनी चाहिए। दक्षिणी एशिया में 'सार्क', 'नाम' व संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अनुकूल वातावरण निर्मित करना चाहिए जिससे आतंकवाद की समाप्ति के साथ ही शांति स्थापना में भी मदद मिल सकेगी।
- दक्षिणी एशियाई देशों को सैनिक प्रतिस्पर्धा नहीं करके अपने क्षेत्र में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी आदि को कम करके जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है।
- आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत को पाकिस्तान से प्रभावी वार्तालाप करनी चाहिए जिसमें जम्मू–कश्मीर के आतंकवादी संगठनों को भी सम्मिलित करना चाहिए क्योंकि इनकी उपस्थिति के बिना सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों से निर्दोष जनता तथा सैनिकों की मौतों का सिलसिला जारी हैं सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए भारत को आंतरिक व बाहरी सुरक्षा के प्रभावी उपाय करने चाहिए।
- श्रीलंका व लिट्टे के बीच संघर्ष में भारत को तटस्थता की नीति नहीं अपनानी चाहिए क्योंकि भारत दक्षिणी एशिया का प्रमुख देश है। लिट्टे व श्रीलंका के बीच संघर्ष श्रीलंका की आन्तरिक राजनीति नहीं है इसका प्रभाव भारतीय राजनीति पर भी पड़ता है। भारत के द्वारा श्रीलंका को विश्वास में लेकर लिट्टे को समस्या की समाधान करना चाहिए।
- बांग्लादेश को अस्तित्व में लाने का श्रेय भारत को है। अतः बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद या अन्य समस्याओं का समाधान करना चाहिए। भारत–बांग्लादेश संघर्ष से पाकिस्तान व चीन को बल मिलता हैं। अतः दोनों देशों को अपनी समस्याएँ आपसी वार्तालाप करके हल करनी चाहिए।
- दक्षिणी एशिया में भारत की स्थिति केन्द्रीय है। इस कारण छोटे पड़ोसी देशों को आर्थिक, वैज्ञानिक, व्यापारिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सहायता देनी चाहिए। मालद्वीप जैसे देश को सामरिक सुरक्षा तथा आर्थिक सुरक्षा देनी चाहिए।
- नेपाल व भूटान को राजतंत्र समाप्त करके सशक्त लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए तथा भारत को बड़े भाई के रूप में देखना चाहिए।
- पाकिस्तान को आतंकवाद व भारत विरोधी नीति का त्याग करके सहयोग की भूमिका निभानी चाहिए जिससे दक्षिणी एशियाई देश विकसित देश की श्रेणी में आ सके।

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दक्षिणी एशिया के प्रति विदेश नीति सहयोगी, विकासपरक, संयमित एवं सृजनशील रही हैं। मनमोहन सिंह ने भी वाजपेयी की विदेश नीति में कुछ परिवर्तनों के साथ अनुसरण किया है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाजपेयी की विदेश नीति को चरम शिखर तक पहुँचाने का कार्य किया है। जो आने वाले समय में भारत एवं दक्षिणी एशियाई देश विश्व पटल पर सशक्त भूमिका निभाने में सफल होंगे।

Copyright © 2017 Published by kaav publications. All rights reserved www.kaavpublications.org

संदर्भ सूची

1. डॉ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा (सम्पादक) : कुछ लेख कुछ भाषण – अटल बिहारी वाजपेयी, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014
2. डॉ. ना.मा. घटाटे (सम्पादक) : अटल बिहारी वाजपेयी – गठबन्धन की राजनीति, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009
3. वी.एन. खन्ना, लिपाक्षी अरोडा : भारत की विदेश नीति, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
4. आर.एस. यादव : भारत की विदेश नीति एक विश्लेषण, किताब महल, इलाहाबाद, 2005
5. डॉ. बी.एल. फड़िया : अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2006
6. जे.एन. दीक्षित : भारत पाक सम्बन्ध (शांति एवं युद्धकाल में), प्रभात पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012
7. यु.आर.घई : भारतीय विदेश नीति, न्यु एकेडमिक पब्लिशिंग कम्पनी, जालन्धर 2004
8. पुष्पेष पंत : भारतीय विदेश नीति, न्यु एकेडमिक पब्लिशिंग कम्पनी, जालन्धर 2004
9. शीला ओझा : भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन, प्रिन्टवेल बुक्स, प्रा.लि., जयपुर, 2000
10. जे.एन. दीक्षित : भारतीय विदेश नीति, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012
11. आर.एस. यादव : भारत की विदेश नीति, डॉर्लिंग किडरस्ले, नोएडा, 2013

KAAV

Copyright © 2017 Published by kaav publications. All rights reserved www.kaavpublications.org